वर्तमान आर्थिक व्यवस्था एक षडयंत्र

सत्तावन वर्ष पूर्व जब से मैने होश सम्हाला तभी से मैं यह मानता हूँ कि वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था गरीबो, ग्रामोणो श्रमजीवियो छोटे किसानो के खिलाफ पूंजी पतियों, शहरियों, बुद्धिजीवियो तथा बडे किसानो का मिला जुला षडयंत्र है। निम्न वर्ग के खिलाफ मध्यम वर्ग को उच्च वर्ग का भी समर्थन प्राप्त है। सत्तावन वर्षो के बाद आज भी अपने उस विचार पर कायम हूं कि मेरे लाख प्रयास के बाद भी यह षडयंत्र मजबूत हुआ है। आज भी गरीब ग्रामोण श्रमजीवो, छोटे किसान के खिलाफ उसी प्रकार योजनाएं बन रही है, जैसे उस समय बनती थी। यदि आबादी के हिसाब से तीन भाग मे बांटा जाय तो करीब चालोस करोड निम्न वर्ग के लोग होगे। चालीस करोड मध्यम वर्ग के और चालीस करोड उच्च वर्ग के । निम्न वर्ग के चालीस करोड में से नब्बे प्रतिशत लोग गरीब ग्रामीण श्रमजीवो छोटे किसान ही होगे। नब्बे प्रतिशत आदिवासी और हरिजन इसी वर्ग में शामिल होगे। गिने चुने आदिवासी हरिजन मध्यम श्रेणी मे होगे । और उच्च वर्ग मे तो शायद ही कोई हो । स्वाभाविक है कि निम्न वर्ग के लोग गांवो मे रहकर श्रम करते हैं और उत्पादन करते हैं जबकि मध्यम श्रेणी के लोग अपक्षाकृत अधिक शहरो में रहकर बौद्धिक कार्य करते हैं अथवा विचौलियो को भूमिका मानते हैं। बुद्धिजीवो वर्ग को यह खूबी होती है कि वह निम्न वर्ग का मार्ग दर्शन भी करता है, गुमराह भी करता है और नेतृत्व भी करता है । यही कारण है कि सत्ता से जुडे लोग मध्यम वर्ग को अपने साथ जोडकर रखना मजबूरी समझते है । भारत का बुद्धिजीवो मध्यम वर्ग कितना कुशल होता है कि उसने निम्न वर्ग के लोगो में जमीन के प्रति एक अजीब मोह पैदा किया और अपने या उच्च वर्ग के अंदर पैसा या सुख सुविधाओ के प्रति। यह प्रचार का ही प्रभाव है कि हर गरीब आदमी जमीन से चिपका रहता है भले ही उसको कोई लाभ हो या न हो । इन बुद्धिजीवियो ने योजना बनाकर निम्न वर्ग के उत्पादन और उपभोग को सब प्रकार की वस्तुओ पर भारी अप्रत्यक्ष कर लगवा दिये। और मध्यम तथा उच्च वग के उपयोग को वस्तुओ पर कर नही लगाए। इन बुद्धिजीवियो ने गांवो मे पैदा होनेवाली वनोपज या पेड पाधे तक पर भारी कर लगा दिये। विदित हो कि सरकार की आय के साधनो मं वनउपज का बहुत बडा योगदान होता है। दूसरी ओर इन लोगो ने शिक्षा का बजट बढाना शुरू कर दिया । हर कोई जानता है कि शिक्षा का निम्न वर्ग को लाभ दस से पंद्रह प्रतिशत ही मिल पाता है और मध्यम वर्ग को पचास से साठ प्रतिशत । परन्तु शिक्षा का बजट बढता चला गया और गांवो मे वनोपज या वन उत्पादन से धन संग्रह को मूख्य आधार बनाया गया। मैनें दिल्ली जाकर महसूस किया कि भले हो राजनेता मेरी बात को न समझें किन्तु ब्रहमदेव शर्मा अरविन्द केजरीवाल, राज गोपाल अमर नाथ भाइ सरीखे लोग तो अवश्य समझेगें कि निम्न वर्ग पर टैक्स लगाकर कृत्रिम उर्जा को राहत देना या शिक्षा पर खर्च करना अमानवीय भी है और निम्न वर्ग के साथ धोखा भी । मैनें बहुत प्रयास किया किन्तु मेरी बात को मानने के लिये कोई तैयार नही । सब मेरी बात को चर्चा में तो स्वीकार कर लेते थे लेकिन घर जाकर फिर पलट जाते थे। क्योकि सबको दिखता था कि इस बात को उठाते ही वे अलग थलग पड जाएंगे। उनका एन. जी. ओ. भी फेल हो जाएगा और उनकी पूछ भी नही रहेगी । अन्य लोग से तो मुझे कोई उम्मीद ही नही थी। लेकिन ऐसे लोगो ने इन विषय पर जरा भी आगे बढने से इन्कार कर दिया। स्थिति तो यहां तक है कि आज भी मेरे साथ काम कर रहे अनेक साथी लोक संसद पर सहमत है। समाज सशक्तिकरण पर सहमत है किन्तु निम्न वर्ग के उत्पादन उपभोग की वस्तुओ पर सब प्रकार के टैक्स हटाकर कृत्रिम उर्जा पर डाल देने के लिये सहमत नही होते। मैं लगातार देख रहा हूँ कि ब्रहम देव शर्मा, राज गोपाल जी निम्न वर्ग के अंदर जमीन के प्रति मोह बढाकर बनाए रखना चाहते हैं। मैं नही समझ पाता कि बडे लोग धन कमावे और गरीब, ग्रामीण खेती करें। यह एक प्रकार का आरक्षण भविष्य में घातक ही होगा। ये सारे लोग किसी भी रूप में न श्रम की मांग बढने देते हैं न श्रम का मूल्य। पहली बार भारत सरकार ने नरेगा चालू किया जिसने गांवो में श्रम की मांग बढाई और मूल्य बढाया। आज हमारे ग्रामोण विकास मंत्री जय राम रमेश नरेगा के विरूद्ध जी जान से लगे हुए हैं। उन्हें श्रम जीवियो का भ्रष्टाचार बहुत अखरता है। उनका मानना है कि चाहे बडे लोग या मध्यम श्रेणी के लोग जो भी करे लेकिन निम्न वर्ग कोई भ्रष्टाचार न करे और उनका बस चले तो वे नरेगा को बन्द भी कर दे। हरियाणा पंजाब के कई सांसदो ने इस संबंध मे प्रस्ताव भी पारित किये हैं कि नरेगा के कारण उत्पादन पर बुरा असर पड रहा है। यह तो मनमोहन सिंह सोनियां गांधी लाल कृष्ण आडवाडी सरीखे कुछ लोंगो की जिद है कि आज भी नरेगा को योजना चल रही है। छत्तीसगढ के मुख्य मंत्री रमण सिंह अन्य मुख्य मंत्रियो की अपेक्षा अधिक संवेदनशील माने जाते है। उन्होने नीति निर्धारण के समय यह बात उठाई कि गावो मे रोजगार बढना चाहिये। उद्योग लगने चाहिये। उन्होने यह भी आदेश दिया कि गांवो में खेती को जमीन का रकबा किसी भी रूप में नहीं घटना चाहिये। मैं आज तक नहीं समझा कि यदि कोई छोटे से छोटा उद्योग भी लगेगा तो वह गांव की जमीन मे लगेगा या हवा मे। स्वाभाविक है कि गांवो मे उद्योग लगाने की बात दिखावटी थी और शहरो मे उद्योग केन्द्रित करने की बात दिल को। इन सब बुद्धिजीवियो आर नेताओ का ठीक से बस चले तो निम्न वर्ग को श्रम करने तक सीमित कर देंगें और मध्यम वर्ग उच्च वर्ग को खाने की छूट कर देंगे। अभी राज गोपाल जी ने जो आंदोलन किया उससे ऐसा लगता है कि निम्न वर्ग को जमीन सें लगाए रखने के लिये बुद्धिजीवियों और राजनेताओं क बीच एक मिली भगत है। ज्योही किसी गांव में कोई उद्याग लगाने की स्थिति पैदा होती है तो ब्रहम देव शर्मा को सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण को चिन्ता शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे पर्यावरण बचाना, अनाज को पैदा करना, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग को सुरक्षा देना, निम्न वर्ग की ठेकेदारी है और हमारे तथा कथित बुद्धिजीवी इस चालोस करोड निम्न वर्ग को उसके दायित्व को याद दिलात रहते है और बदले मे उन्हे कुछ सस्ता अनाज सस्ती जमीन देकर उनके हित चिंतक बने रहते है। किसी गांव में एक एकड किसी आदिवासी को जमीन है तो उसका मूल्य दो हजार रूपये से ज्यादा का नही होगा। और उसके ठीक बगल में किसी गैर आदिवासी की जमीन हो तो उसका मूल्य कई लाख रूपये होगा क्योकि गैर आदिवासी के पास पैसा है और आदिवासी के पास जमीन । आदिवासी को यह अधिकार नही है कि वह जमीन के बदले में पैसा रख ले । यह प्रचारित कर दिया गया है कि निम्न वर्ग के लोग मूर्ख होते है। उनके हाथ में पैसा जाएगा तो बर्बाद कर देगे। जमीन रहेगी तो कई पीढियो तक काम आएगी। इसलिये उनके पास जमीन सुरक्षित रहनी चाहिये और उच्च मध्यम वर्ग के पास पैसा। सब मानते है कि यदि कृत्रिम उर्जा का मूल्य दो गुना कर दिय जाए, उससे प्राप्त धन चालीस करोड निम्न वर्ग के लोगो मे बाट दिया जाए तो निम्न वर्ग के प्रति परिवार को दस हजार रूपया प्रतिमाह तक मिल सकता है। मध्यम वर्ग का मानना है कि इससे उच्च मध्यम वर्ग परेशान हो जाएगा। आवागमन महंगा हो जाएगा। निम्न वर्ग मेहनत करना बंद कर देगा आर यदि निम्न वर्ग इतनी मेहनत नही करेगा तो मध्यम वर्ग बैठकर खाएगा कैसे। ममता बनर्जी तो निम्न वर्ग के खिलाफ षडयंत्र करती रहती है कि आवागमन मंहगा न हो शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट न घटे। भले ही रोटी, कपडा, मकान, दवा, पर टैक्स बढाना पडे या न पडे। लालू प्रसाद, राम विलास पासवान, ममता बनर्जी सब जानते हैं कि सस्ते आवागमन का लाभ निम्न वर्ग को 10 प्रतिशत से अधिक नही होगा। मध्यम वर्ग ही इसका ज्यादा लाभ उठाता है। लेकिन इन नेताओं का मानना है कि निम्न वर्ग जाएगा कहा। चाहे भाजपा के पास जाये या कांग्रस के पास। सब जगह तो मध्यम वर्ग का ही एकाधिकार है। अब समय आगया है कि मध्यम वर्ग के कुछ लोग इस बात को समझे। कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि होनी ही चाहिये । लकडी पर टैक्स लगाकर रसोई गैस पर सब्सीडी देना बहुत बडा पाप है। चाहे अरविन्द केजरीवाल, राज गोपाल, अमर नाथ भाई इस बात को समझे या न समझे । लेकिन अन्य लोगो को तो समझना चाहिये कि निम्न वर्ग मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के बीच बढती हुई दूरी को एक सीमा आवश्यक है। भारत की विकाश दर यदि छ प्रतिशत हो तो निम्न वर्ग की

विकास दर 1 प्रतिशत होना मध्यम वर्ग की 6 प्रतिशत हाना उच्च वर्ग की 12 प्रतिशत होना किसो भी रूप मे न्याय संगत नही है। विकाश दर का यह अंतर कम होना ही चाहिये। यह मानवीय दृष्टि से भी उचित है और देश काल परिस्थिति के अनुसार भी ।

1 प0 मृत्युंजय शर्मा भिलाई

आज ही ज्ञान तत्व मिला । मैं सारा काम भूलकर उसे आध्यापान्त पढ जाता हूँ । आप राहुल के बारे मे सोच कर लिखकर क्यो अपना वक्त बरबाद कर रहे हैं। अब कांग्रेस को मौका नही मिलेगा। गांधी को आप पिछली सदी का ही क्यो रहने देना चाहते है। अन्ना की हवाई यात्राा समयाचित थी। निश्चित रूप से आप को सोंचना चाहिए कि अन्ना अब राजनीति में प्रवेश हेतु अपनी टीम को छोडकर गांधी की तरह अलग हो रहे हैं। देश भ्रमण यदि करेंगे तो निश्चय ही हवाई यात्रा नही करेंगे । सबसे बडी चूक हो रही है चुनाव पद्धति में गडबडी। चुनाव आयुक्त आदि का चयन सर्व दलोय निणय से होना चाहिये।

उत्तर–वर्तमान मे राजनैतिक रूप से दो ही दल है। जेडीयु और भारतीय जनता पार्टी । बाकी सब तो किन्ही व्यक्तियो के गिरोह है। इन्ही मे अरविन्द केजरीवाल का भी दल है । यह भी उसी तरह है जैसे दल माइनस अरविन्द बराबर शून्य। जिस तरह बसपा मे मायावती है या कांग्रेस माइनस नेहरू परिवार । यदि संवैधानिक दर्ष्टि से विचार किया जाए तो भाजपा एक राजनैतिक दल होते हुए भी स्वशासन देने के विषय में सोच भी नही सकती। क्योकि उसका जन्म ही संघ की केन्द्रीयकरण को नीति से हुआ है। कांग्रेस पार्टी नीति के मामले में स्वशासन को स्वीकार करती है। किन्तु वह राजनैतिक दल न होकर नेहरू परिवार का गिरोह मात्र है। यह हमारे लिये एक सकट का समय है कि देश क्या करे? यदि कांग्रेस पार्टी पारिवारिक गिरोह से निकल सके तो सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं। किन्तु वह निकलना नही चाहती। स्वशासन के विस्तार का समाधान नरेन्द्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी मे दिखाई नही देता। जो राजनैतिक दल समाज को जगह राष्ट्र या धर्म को बडा मानता है उसकी बुनियादी सोच ही गलत है। इसलिये वर्तमान समय में राजनैतिक घटना क्रम का समाधान मनमोहन सिंह नीतीश कुमार अरविन्द केजरीवाल जैसा के माध्यम से खोजने के प्रयास किये जा रहे हैं। आपका मानना है कि चुनाव आयुक्त, सी बी सी आदि का चयन सर्वदलोय हो। स्पष्ट दिखाई देता है कि समाज को तो तोडने मे सभी दलो को समान सहमति है। कोई भी दल समाज को एक जुट नही होने देना चाहता। ऐसी स्थिति मे हमारो पहल यहां से शुरू होनी चाहिये कि हम संसद रूपी जेल खाने से संविधान रूपी अपने भगवान को मुक्त करा सके। जब संविधान राजनेताआ के चंगुल से मुक्त होकर समाज की पहुच के अंदर आ जायेगा तब राजनेताओ की उच्श्रखलता पर लगाम लगेगी। अभी तो रावण के नाभि मे अंमृत है। बिना अमृत कुंड पर आक्रमण किये हम रावण का कुछ नही बिगाड सकते। रावण जान दे देगा । लेकिन उस अमृत कुण्ड पर आक्रमण नहो होने देगा। हमने लोक संसद की आवाज उठाकर उस अमृत कुण्ड पर ध्यान केन्दित करना शुरू किया है। अच्छा हो कि हम सब मिलकर लोक संसद को आवाज से ही राजनैतिक परिवर्तन को शुरूआत करे।

2 कृष्ण लाल रूँगटा पो0 चिरकुण्डा :828202

प्रश्न– विगत लगभग एक वर्ष से आप लोक संसद की चर्चा कर रहे है और लोक स्वराज पर आधारित जिस व्यवस्था परिवर्तन को लेकर हम सभी संघर्ष कर रहे हैं उस दिशा में आप इसे एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं और इस प्रस्ताव को भारत की वर्तमान राजनैतिक समस्याओं के समाधान के रूप में देखते है । पर मुझे लगता है कि आज देश जिस दौर से गुजर रहा है , उसमें लोक संसद का प्रस्ताव न तो प्रासांगिक है न व्यवहारिक । हम सभी जानते है कि आजादी के बाद हमने प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र को अपनाया और पिछले 65 साल का अनुभव यह बताता है कि लोकतंत्र के इस ब्रांड में लोगो के लिये कोई स्थान नहीं है । नौकरशाहों की, नौकरशाहों द्वारा और नौकरशाहों के लिये सरकार ,इसमें आखिर लोकतंत्र कहॉ है ? लोक संसद की अवधारणा भी प्रतिनिधित्मक है । मुझे इसमें वे सारे अवगुण दिखाई पड़ रहे है जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में है और लोकसभा के सदस्यों की तरह लोक संसद के सदस्यों के चुनाव के लिये भी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रावधान/प्रस्ताव कर आपने उनमें उन सारे दाषेा एवं अवगुणों के आने का रास्ता भी साफ कर दिया है । यदि सरकार आज इस प्रस्ताव को मानकर चुनाव करवाये तो मुझे लगता है कि कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग वही लोग चुनाव जीत कर जायेंगे जो उस क्षेत्र से लोकसभा के लिये चुने गये सांसद के रिस्तेदार या चहते होगे या राजनैतिक दलों के द्वारा समर्थित होगे, भले ही उसका स्वरूप निर्दलीय हो । लोक सांसद का कोई कार्यालय, स्टाफ,आवास तथा वेतन न होने का प्रावधान अर्थहीन है , क्योंकि मै मानता हूँ कि यदि होने वाले आगामी चुनाव में लोकसभा के सांसदों के लिये भी यही प्रावधान लागू कर दिये जाय , तो भी चुनाव उतने ही मंहगे होगे जितने आज है । महत्व कार्यालय, स्टाफ ,आवास तथा वेतन का नही है , महत्व तो 10 लाख मतदाताओं के प्रतिनिधि होने का है। इतने बडे मतदाताओं के वर्ग का प्रतिनिधि बनना ही उसे पावरफुल बना देता है और Power corrupts a man ,इससे तो आप भी सहमत है।

लोक संसद बनने से वर्तमान संसद दादागिरी नही कर सकेगी या सांसद अपने वेतन में मनमानी वृद्धि न कर सकेंगे ,यह मान्यता न सिर्फ खोखली प्रमाणित होगी, बल्कि लोकसभा एवं लोकसंसद मिलकर बचे खचे अधिकारों की भी छोनाझपटी में लग जायेगे । इसलिये अब सबसे पहले सत्ता के अकेन्द्रियकरण की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब हमें लोक संसद की नही, बल्कि सीधे सीधे सत्ता जनता के हाथों में आए अर्थात अधिकारों का विकेन्द्रियकरण हो,संविधान में संशोधन कर व्यक्ति, परिवार, गॉव, जिला, राज्य व केन्द्र के अधिकारो की सूचो जोड़ी जाय इस एक सूत्री मॉग को लेकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। एक लंबे विचार मंथन के पश्चात विगत 15 वर्ष पूर्व बनाये गये भारत के नये संविधान के आधार पर नई व्यवस्था बनाने के लिये वैचारिक ढॉचा खडा करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है ।

उत्तर– मैं आपके पूरे विचार से सहमत हूँ । मैं नही मानता कि लोक संसद कोई समाधान है । मै मानता हूँ कि आज देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें संसदीय लोकतंत्र को जगह सहभागी लोकतंत्र ही समाधान है। लोक स्वराज मंच का उददश्य है कि वर्तमान सविधान मे संशाधन करके उसे सहभागी लोकतंत्र को दिशा दी जाए। ऐसे संशोधित संविधान का प्रारूप भी हमने प्रसारित कर दिया है किन्तु प्रश्न यह है कि जब तक संसद में हमें पूर्ण बहुमत प्राप्त नही होता तब तक हमारे लोग सिर्फ जनमत जागरण ही करे या कोई छोटा मुद्दा लेकर संघर्ष भी शरू करे ? कल्पना करिये कि हमारे दो चार लोग संसद मे चले जाए तो वे संशोधित संविधान क लिए जनमत तो खडा करेंगे। लेकिन वर्तमान संसद में वे लोक संसद के लिए अंदोलन करेंगे। हम वर्तमान संसदीय लोकतंत्र से छेड़ छाड अथवा उसकी उंगली पकडने तक ही लोक संसद को मानते है । जिस तरह स्वंतत्रता संघर्ष में अनेक छोटे छोटे आंदोलन हुए थे, समझौते हुए थे, जो संघर्ष को आगे बढाने में सहायक तो थे लेकिन संघर्ष नही, हमारे विचार मे लोक संसद का मुद्दा लोकतंत्र के लिए संघर्ष के एक प्रारंभिक कदम के रुप मे होगा । आपन लोकसंसद के विचार में जो प्रश्न खडे किये है उन

सारे प्रश्नों से हम सहमत भी है और अवगत भी । हम तो मात्र वर्तमान स्थिति से टकराव को शुरुआत के लिए लोकसंसद का मुद्दा उठा रहे हैं । लोक संसद किसी समस्या का समाधान नही है बल्कि वर्तमान संसदीय लोक तंत्र के खिलाफ जनमत जागरण का एक प्रारंभिक चरण मात्र है।

खबरे इस सप्ताह की 16 से 22 अक्टूबर दो हजार बारह

इस सप्ताह के प्रारंभ में ही बाबा रामदेव के विरूद्ध मामला प्रकाश मे आया। उत्तरांचल सरकार ने बाबा रामदेव के गुरू शंकर देव जी के रहस्य मयी ढंग से गायब होने की घटना की सी बी आई जांच का आदेश देकर बाबा रामदेव की दुखती रग पर हाथ रख दिया। बाबा बौखला गये । उन्हे चाहिये था कि वे जांच के लिये चाहे अंदर अंदर कितने भी भयभीत क्यो न हो किन्तु प्रत्यक्ष रूप से प्रसन्नता व्यक्त करनी थी किन्तु किया उन्होने ठीक उल्टा। उन्होने यहां तक कह दिया कि यह सरकार लाल बहादुर शास्त्री , श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीन दयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस जैसे देश भक्तो की हत्या की तो जांच नही करवाती और एक सामान्य सी घटना को बुरो नीयत से तूल दे रही है। बाबा की बौखलाहट से प्रमाणित होता है कि इस घटना मे कोई न कोई रहस्य अवश्य है।

वैसे भी बाबा रामदेव कभी सन्यासी नही रहे । बाबा रामदेव, स्वामी अग्निवेष, उमा भारती सरीखे लोग गेरूआ वस्त्र धारी तो कहे जा सकते है किन्तु सन्यासी नही। इन्हे राज सन्यासी जैसा नाम भी दे सकते है। सन्यासी की एक विशेष पहचान होती है कि वह यम नियम का अधिकाधिक पालन करने वाला हो। इन राज सन्यासियो को यम से कोई मतलब नही । यम के पाच सूत्र अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रहमचर्य अपरिग्रह का पालन करने का दायित्व तो समाज को है। ये तथा कथित राज सन्यासी तो स्वयं को समाज से भी उपर मानते है। कितने दुख को बात है कि हमारे एक सन्यासी पर अपने गुरू के गायब करने का आरोप लगे और समाज मे कोई हलचल न हो । यहां तक कि समाज पूरा मामला स्पष्ट होते तक उक्त सन्यासी को संदेहास्पद मानता हो तो ऐसे तथाकथित सन्यासी को या तो गेरूआ वस्त्र उतार देना चाहिये या किसी नदी मे ..... चाहिये। बाबा रामदेव सरीखा सम्मानित सन्यासी, जिसने कुछ वर्ष पूर्व ही भारतीय धर्म व्यवस्था को विश्व स्तर तक पहुंचाने का प्रशंसनीय काम किया था वही बाबा इतने कम समय मे ही इस तरह औधे मुंह गिर जायगा ऐसा तीव्र पतन सोचा नही गया था। इससे तो कई गुना अच्छे हमारे अन्ना जी है जिन्होने गृहस्थ वस्त्रो मे होते हुए भी सन्यासियों के उच्च कीर्तिमान बनाये रखे है।

दूसरी घटना विहार प्रदेश के मधुबनी जिले की है। मधुबनी का एक युवक प्रशान्त एकाएक गायब हो जाता है। कुछ दिनो बाद ही एक सिर कटी लाश मिलती है जिसे प्रशान्त के माता पिता देखकर बतात है कि लाश प्रशान्त की ही है। लाश की मांग की जाती है। पुलिस अब तक आश्वस्त नही है कि लाश प्रशान्त की ही है। जोर आजमाइश शुरू होती है । प्रशान्त के माता पिता के पक्ष मे छात्र समुदाय तथा सभी विपक्षी दल सामने आते है तो दूसरी आर खडा है प्रशासन और डरे सहमे बेचारे नीतिश । आंदोलन उग्र होता है और गोली चलती है जिसमे दो छात्र मारे जाते है। विपक्ष घटना के विरोध मे विहार बंद कराता है। ट्रेन रोकी गई। लालू राम विलास ऐसे प्रदर्शन कर रहे थे जैसे कि अब उन्हे गद्दी मिलने ही वालो हेा। सभी टी वी चैनल तथा अखबार नीतिश कुमार के विरूद्ध दिन रात एक से बढकर एक टिप्पणो कर रहे थे। इस सारे घटना क्रम के बीच घटनाओ ने एकाएक यू टर्न लिया जब प्रशान्त दिल्ली मे अपनी प्रमिका के साथ जीवित मिल गया । सांप सूंघ गया सबको ।

भारत का मीडिया पिछले कुछ महिनो से नीतिश कुमार क खिलाफ लगातार वातावरण बना रहा है। प्रशान्त के मामले मे भी मीडिया ने बहुत जोरदार तरोके से नीतिश के खिलाफ वातावरण बनाया परन्तु जब घटनाए बिल्कुल य् टर्न ले बैठी तो मीडिया को कम से कम अपना सम्मान बचाने के लिये तो कुछ दस बोस प्रतिशत प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिये थी। सम्पूर्ण समाज मे एक उल्लेखनीय प्रश्न खडा करने वाली घटना इस तरह शान्त होगई जैसे यह कोइ महत्वपूर्ण मुद्दा न हो। इसी एक अफवाह पर आंदोलन का खडा होना, गोलियों का चलना, मृत्यु होना, विहार बंद होना और फिर घटना का अफवाह प्रमाणित होना कोई साधारण घटना नही थी । प्रशान्त के बरामद होते ही मीडिया ने खबर प्रकाशित करके चुप्पी साध ली । अरविन्द केजरीवाल सलमान खुर्शीद गडकरी जैसे घिसे पिटे मुद्दो पर प्राइमटाइम चलाने वाला मीडिया इस मुद्दे पर तो चुप्पी साध गया। लाश प्रशान्त की ही है इस बात को ठीक से समझे बिना इस तरह तूल देना समझ मे ना आने वाली बात है। जिन लोगो ने गोली चलाने का वातावरण बनाया, विहार बंद करवाया , सारे बिहार को अशान्त किया, उनलोगो को कटघरे मे खडा करने मे मीडिया इतना पीछे क्यो है? मेरे विचार से तो इस घटना के बाद स्पष्ट प्रमाणित होता है कि नीतिष कुमार के खिलाफ भारत की राजनीति मे एक गुप्त षडयंत्र चल रहा है। मेरा यह मत है कि बिहार की इस घटना पर सम्पूर्ण भारत मे एक सार्थक बहस छिडनी चाहिये और इस बहस को किसी परीणाम तक ले जाना चाहिये।

तीसरो घटना के रूप मे इस सप्ताह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन गडकरी के विषय मे भूमि संबंधी रहस्य उदघाटन था । मै नही समझता कि इसमे कोई नई बात थी। भारत के हर राजनेता राजनीति का व्यापार समझता है । कुछ गिने चुने लोग ही है जो इसे व्यक्तिगत या पारिवारिक व्यवसाय न मानकर एक दलगत राजनैतिक व्यवसाय मानत है। ऐसे आंशिक रूप से अच्छे लोगो मे नीतिन गडकरी का नाम कभी नही रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिये भी यह मजबूरी है कि उसे ऐसे व्यवसायियों से साठ गाठ करनी पडती है । नीतिन गडकरी इतने बडे व्यवसायी है यह पहले तो देश को पता नही था लेकिन अब मालूम हो गया । इतना तो पहले से ही मालूम था कि नीतिन गडकरी जोड तोड मे माहिर है और इसलिये उन्हे ऐसी बडी जिम्मेदारी दी गई है, किसी उचे चरित्र के आधार पर नही। जब सम्पूर्ण राजनीति का ही व्यवसायी करण हो चुका है तो अगर नीतिन गडकरी ने भी अपने व्यवसाय के लिये राजनीति का उपयोग किया तो इसम कोई विशेष परंपराये नही टूटी है। नीतिन गडकरी एक अच्छे वकोल भी दिखाई देते है। बडो सफाई से उन्होने कहा कि बांध का एक प्रतिशत से भी कम पानी उनके फैक्ट्री को मिला है। जब हमलोगो ने पता किया तो सच्चाई सामने आयी कि उस बांध से एक प्रतिशत से भी कम पानी ही बाहर निकल पाया है जो किसी सिचाई करने वाले को एक बूंद भी नही मिला है। इसी तरह उन्होने और इनके सहयोगियो ने कहा कि अंजली दमानिया, जिसने यह पोल खोली है, उसने भी अपनी जमीन का लैड यूज बदलकर अधिक रेट मे बेचा है। गडकरी जी और उनके साथियो ने यह नही सोचा कि अंजली दमानीया ने यदि लैड यूज बदला है तो वह सरकारी कानून का उलंधन है । सामाजिक कानून का नहीं । उन्होने किसी जनता द्वारा प्राप्त पद का दुरूपयोग नही किया है। जबकी गडकरी जी सांसद है, राजनैतिक दल के अध्यक्ष है, सामाजिक राजनीति के अगुआ है । नीतिन गडकरी ने एक व्यवसायी होने के नाते यह लाभ प्राप्त नही किया है । बल्कि एक राजनैतिक पद प्राप्त व्यक्ति के नात प्राप्त किया है। इसलिये नीतिन गडकरी ओर दमानिया के बीच किसी प्रकार की कोई तलना नही हो सकती । सच बात तो यह है कि टीम अरविन्द यह सिद्ध करने मे यह सफल रही है कि आम तौर पर सभी राजनैतिक नेता अलग अलग दलो मे होते हुए भी अपने व्यक्तिगत पारिवारिक या व्यावसायिक हितो की सीमाओ को अच्छी तरह समझते है और उनका पालन करते है।

इसी बीच सलमान खुर्शीद भी सुखियो मे छाये रहे। सातो दिन एक एक करके सलमान खुर्शीद गल्तिया करते रहे जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी का ज्यादा और भारतीय जनता पार्टी को आंशिक रूप से होता रहा । साथ ही पूरा लाभ टीम अरविन्द के खाते मे गया । खुर्शीद परिवार के प्रेस कान्फ्रेन्स से यह सिलसिला शुरू हुआ और समापन होते होते तो उन्होने अनेक तरह की धमकिया तक दे दी। कोई नेता घपले करे यह कोइ बहुत अचंभे की बात नहो है। लेकिन कोई नेता घपले करे, पकडा जाए, और उसके साथ साथ दबंगई भी करे तो अवश्य ही चिन्ता को बात है । सलमान खुर्शीद सरीखा व्यक्ति कानून मंत्री रहते हुए जिस तरह की भाषा बोल रहा था उससे सौ गुना अधिक शालोन भाषा तो उनकी पत्नो लुइस खुर्शीद को थी। जिस तरह एक व्यक्ति के कथन पर कानून मंत्री प्रसन्न होकर तालिया बजाने लगे वह तो उनके पतन के पराकाष्ठा ही थी। भारत के लोकतंत्र का सिर उस समय शर्म से झुक गया जब भारत का कानून मंत्री कानून मंत्री को हैसियत से घोषणा करता है कि अरविन्द केजरीवाल का फरूखाबाद से लौटना कठिन हो जाएगा तो सबकुछ देखकर सुनकर ऐसा लगा जैसे हम किसी फिल्म मे किसी खलनायक का पार्ट करने वाल व्यक्ति को बाते सुन रहे है । भारत की जनता को इस बात का संज्ञान लेना चाहिये ।

इस सप्ताह और एक नई घटना देखने को मिली कि मनमोहन सिंह सरकार ने कुछ और कदम मजबूती से आगे बढाया । राजस्थान मे उन्होने आधार कार्ड योजना पर आये संदेह के बादलो को दूर कर दिया ओर यह भी कहा कि कैसे कैश सब्सीडी योजना लागू को जाएगी। मै व्यक्तिगत रूप से ऐसा समझता हूँ कि नरेगा के बाद आधार योजना को मजबूतो से लागु करना तथा कैस सब्सीडी को शुरू करने की योजना की घोषणा एक बहुत बडी हिम्मत का काम है। अनेक पेशेवर लोग नरेगा, आधार कार्ड, कैश सब्सीडी, जैसी दोष रहित योजनाओ का भी किसी न किसी नाम पर विरोध करते रहे हे । जहा अटल जी को सरकार ऐसी योजनाओ को अच्छा समझतें हुए भी बोच मे हो छोड देती थी वही मनमोहन सिंह सरकार ने ऐसी अच्छी योजनाओ को लाग् करने मे दृढता का परिचय दिया है । भूमि अधिग्रहण संसोधन कानून भी ठीक दिशा मे बनेगा ऐसी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई नई योजना नही है। वह तो सिर्फ गाय, गंगा, मंदिर तक चिपटो रहती है । लेकिन कांग्रेस पार्टी विशेषकर मनमोहन सिंह के कार्य काल मे ऐसी नई नई लाभदायक योजनाए लागु करने का श्रेंय प्राप्त कर रही है।

खबरें इस सप्ताह की 23.10.2012 से 31.10.2012

इस सप्ताह के प्रारंभ में ही कांग्रेस महा सचिव दिग्विजय सिह जी ने यह बयान देकर सबको चौका दिया कि बहुत पूर्व से ही कांग्रेस के लोग अटल जी तथा आडवाणी जी के रिश्तेदारों द्वारा सत्ता के दुरूपयोग के विषय में जानते थे किन्तु उन्होंने कभी वे मुद्दे नहीं उठाये क्योंकि राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच एक सीमा रेखा होती है। कांग्रेस पार्टी ने उस सीमा रेखा का हमेशा सम्मान किया है किन्तु आज विपक्ष उस सीमा का उल्लंघन कर रहा है। दिग्विजय सिंह का यह बयान अत्यन्त महत्वपूर्ण था किन्तु मीडिया ने इस गंभीर बयान को ज्यादा महत्व नहीं दिया। संभव है कि राजनैतिक दलों ने दिग्विजय सिंह की इस मूर्खता पूर्ण सच्चाई की स्वीकारोक्ति को राजनैतिक व्यवसाय के लिये हानिकर समझा हो और उसे दबाने के लिये मीडिया से विशेष अनुरोध किया हो।

विदित हो कि पिछले कई माह से इस व्यवसाय में शामिल होने की दौड़ दौड़ रहे अरविन्द केजरीवाल ने कई बार सत्ता और विपक्ष पर मिलजुल कर नूरा कुश्ती का आरोप लगाया था। यह बात कई बार सामने आई कि भाजपा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ लगाये जा रहे अनेक आरोप पहले से ही फिक्स होते हैं जिनकी सीमाएँ तय होती हैं। अरविन्द जी के इन आरोपों के कारण भारतीय जनता पार्टी अपनी विपक्ष की विश्वसनीयता खोती जा रही थी और वह स्थान धीरे धीरे अरविन्द केजरीवाल समूह को मिलने लगा था। तिलमिलाई भाजपा ने वाड्रा मामले में कुछ कदम बढ़ाये तो तिलमिलाये दिग्विजय सिंह जी ने उन्हें सीमा रेखा की याद दिलाई।

मैं अब भी मानता हूँ कि अरविन्द केजरीवाल की बढ़ती लोक प्रियता से दोनों ही दल सशंकित हैं। पिछले कई वर्षों से सभी राजनैतिक दल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक दूसरे के सुरक्षा कवच बने हुए थे। अब उन सबके समक्ष संकट है कि या तो वे अरविन्द केजरीवाल समूह को भी इस व्यवसाय का एक प्रतिद्वंदी स्वीकार करें अन्यथा यदि अरविन्द इसी तरह ग्राहकों के समक्ष रहस्योद्घाटन करते रहे तो सबकी दुकानदारी पर ही खतरा हो सकता है।

विदित हो कि इसके पूर्व भी जब संसद में लोकपाल पर बहस चल रही थी तब मुलायम सिंह, शरद यादव तथा लालू यादव ने सम्पूर्ण राजनैतिक जमात को इस खतरे के प्रति सचेत किया था। दिग्विजय सिंह जी ने भी उतनी ही इमानदारी से सचेत किया है। अमरसिंह जी ने इस प्रवृत्ति के प्रति गहरी चिन्ता व्यक्त की है। अब भाजपा को सोचना है कि वह कौन सी राह पकड़े? यदि उसने राजनैतिक व्यवसाय की चिन्ता की तो उसका विपक्ष का दर्जा भी छिन सकता है तथा उसके स्वयं के भ्रष्टाचार की भी पोल खुल सकती है। दूसरी ओर यदि उसने राजनैतिक मर्यादाए बनाये रखीं तो अरविन्द केजरीवाल का संकट है। देखिये कि भाजपा कौन सी राह पकड़ती है।

इस सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को किसी दुर्घटना या हत्या के बदले में (जनसत्ता तेइस अक्टूबर) चार लाख रूपये मुआवजे की घोषणा की है। समझ में नहीं आता कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में दुर्घटना और हत्या को एक ही तराजू पर तौलने की भूल क्यों की गई। मुलायम सिंह जी जब तक मुख्य मंत्री थे तब तक तो दुर्घटना और हत्या में कोई ज्यादा अन्तर नहीं माना जा सकता था किन्तु अब तो अखिलेश मुख्यमंत्री हैं। उन्हें तो दोनों के बीच का फर्क समझना चाहिये।

सुरक्षा सरकार का दायित्व है और दुर्घटना रोकना उसका स्वैच्छिक कर्तव्य। सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। जब लालू, मुलायम, ममता और मायावती सरीखे लोग सत्ता में आते हैं तब दायित्व और कर्तव्य के बीच की दूरी समाप्त कर दी जाती है और सुरक्षा की जगह जनकल्याण का नारा जोर शोर से बुलन्द करना शुरू हो जाता है। पण्डित नेहरू काल से लेकर अब तक ऐसा ही चलता रहा जब डकैती हत्या से पीड़ित की अपेक्षा सांप काटने, रेल एक्सीडेंट या आग लगने से मृत्यु में ज्यादा मुआवजे का प्रावधान बना। पिछले तीन चार वर्ष से जबसे मनमोहन सिंह दुबारा प्रधानमंत्री बने हैं तबसे सुरक्षा पर कुछ विशेष ध्यान दिया गया। यहाँ तक कि कांग्रेस महा सचिव दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को गुमराह करके नक्सलवाद की रोकथाम में रोड़े अटकाने की कोशिश की तथा उस समय के गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् को गति कम करनी पड़ी किन्तु फिर भी प्रयत्न जारी रहे। अब जमाना बदल चुका है। अखिलेश यादव सिर्फ मुलायम पुत्र ही नहीं है। वे तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी ह। उन्हें सुरक्षा और घटना के बीच तथा दायित्व और कर्तव्य के बीच अन्तर करना ही होगा अन्यथा उनकी गिनती भो उन्हीं लोगों में होने लगेगी जैसी इसके पूर्व होती रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे मामलों में अकेली नहीं है। दिल्ली सरकार ने भी एक विज्ञापन के द्वारा भूकम्प, सड़क दुर्घटनाओं को आतंकवाद के साथ जोड़ने की गंभीर गलती की है। दिल्ली सरकार को भी इस संबंध में समझना चाहिये कि जनकल्याण सरकार का दायित्व नहीं है किन्तु सुरक्षा और न्याय सरकार का दायित्व है। कोई भी सरकार अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकती।

इस सप्ताह एक और घटना घटी जब सांसद सुब्रमन्यम स्वामी ने राहुल सोनिया की प्रत्यक्ष पोल खोलते हुए आरोप लगाया कि यंग इन्डियन कम्पनी में सोनिया राहुल के चौहत्तर प्रतिशत शेयर हैं। उक्त कम्पनी को कांग्रेस पार्टी ने नब्बे करोड़ का कर्ज दिया जो नियम विरूद्ध था। यहॉ तक कि राहुल गांधी ने चुनाव लड़ते समय प्रस्तुत शपथ पत्र में उक्त शेयर के विवरण को भी छिपाया। सुब्रमन्यम स्वामो के आरोपों पर सभी कांग्रेसी भी चुप हैं और स्वयं राहुल गांधी भी। अब तक किसी ने आरोपों का कोई सार्वजनिक उत्तर नहीं दिया। वही घिसी पिटी तीन बातें कही गइ (1) हम निर्दोष हैं (2) कानून अपना काम करेगा (3) हम आरोप लगाने वाले पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। वैसे तो वाड्रा प्रकरण ने ही राहुल गांधी का राजनैतिक भविष्य चौपट कर दिया था किन्तु इस शेयर प्रकरण के सामने आने के बाद तो अब मनमोहन सिंह की तुलना में राहुल गांधी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखते।

प्रतिक्रिया स्वरूप बम्बई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं न सुब्रमन्यम स्वामी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन ने तो और भी ज्यादा पोल खोल कर रख दी। ऐसा लगा जैसे प्रदर्शन कारी किसी राजनैतिक दल के कार्यकर्ता न होकर किसी परिवार के कर्मचारी मात्र हों जो अपने मालिक के पक्ष में अपनी रोजी रोटी तक सक्रिय हों। सुब्रमन्यम स्वामी ने आरोप लगाये हैं। सच और झूठ का निर्णय या तो कानून करेगा या समाज। सुब्रमन्यम स्वामी ने आरोप लगाने में शालीन भाषा का प्रयोग किया। फिर विरोध प्रदर्शन किस बात का? क्या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के पास प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं। प्रदर्शनों से तो कुछ ऐसा ही लगता है।

राजनेताओं द्वारा हर आरोप के उत्तर में एक बात और कही जाती है कि यह मीडिया ट्रायल है जो गलत परम्परा है। इस कथन में चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों समान हिस्सेदार हैं। जिन पर आरोप लगे हैं वे कोई सामान्य अपराधी नहीं। उनके पास समाज की अमानत है। समाज अपनी अमानत के विषय मे हर समय सच्चाई जानने का अधिकार रखता है। आप कानून या न्यायालय के नाम पर कानून की मार से तो बच सकते हैं किन्तु सामाजिक विश्वसनीयता की मार से नहीं बच सकते। आपको भी मालूम है कि चुनाव जीतने के लिये सामाजिक विश्वास सबसे अधिक महत्व रखता है। आप न्यायालय से निर्दोष सिद्ध होने के बाद भी समाज की नजरों में तब तक दोषी हैं जब तक आप मीडिया ट्रायल में निर्दोष प्रमाणित नहीं होते।

पहले हम सामान्य लोग नहीं समझ पाते थे कि आज सम्पूर्ण भारत में लोग राजनैतिक शक्ति के पीछे इस पागलपन की सीमा तक पीछे क्यों पड़े हैं? मरने मारने की सीमा तक क्यो उतारू है? किसी व्यक्ति को आप गांधी जैसा सम्मानित पद भी दे दें तो वह उस पद को एक साधारण राजनैतिक पद की तुलना में ठुकराने को तैयार है। नेहरू से लेकर राहुल प्रियंका तक सभी मरे जा रहे हैं किसी राजनैतिक पद के लिये। आप राहुल को चाहे राष्ट्रपति पद दें या राष्ट्रपिता। उसे नहीं चाहिये प्रधान मंत्री के अलावा कुछ और। अब जब से इन नेताओं की पोल खुलने लगी है तबसे यह साफ होने लगा है कि राजनैतिक लोग इन राजनैतिक पदो के पीछे क्यों प्राण दिये जा रहे हैं। अब पता चला कि यहॉ असीम भ्रष्टाचार के अवसर उपलब्ध हैं। जिन्हें जेल में होना चाहिये वे सत्ता सम्पत्ति सम्मान के उच्च सिंहासन पर बिराजमान हैं। अब ये लोग मीडिया के सामने आने से मुंह चुरा रहे हैं। इनके एजेन्ट नुमा लोग मीडिया के सामने कुछ भी उत्तर दे रहे हैं। राहुल, सोनिया, गड़करी, खुर्शीद के मामलों के बाद अब किसी अन्य की चर्चा ही व्यर्थ है।

खबरे इस सप्ताह की 1/11 से 7/11/2012

इस सप्ताह सोनियां राहुल के घोटाले भी सामने आये तो गडकरी जी के भी। इस सप्ताह ही महाराष्ट्र का दस अरब का मध्यान्ह भोजन घोटाला भी खुला तो मीडिया के एक चैनल द्वारा जिन्दल स्टील से सौ करोड रूपया मांगने का स्टिंग भी सामने आया। घोटालों की बाढ मे हर साफ सुथरे चेहरे गले तक डूबते नजर आये। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह जी ने साफ किया कि इस तरह यदि बाल की खाल निकाली जायगी तो सार्वजनिक जीवन का एक भी व्यक्ति साफ नही बच पायगा। कुछ केन्द्रीय मंत्रियों ने भी ऐसी ही गुहार लगाई । मुझे तो इन नेताओ की चिन्ता देखकर मजा आ गया। अब तक इन नेताओ को सामान्य लोगों के लिये नये नये कानून बना बना कर उनका मान मर्दन करने मे बहत मजा आता था। मै स्वयं भुगत चुका हूॅ जब मेरे गोदाम मे अपना एक सौ दस किलो चावल जप्त करके मुझे अठारह दिन जेल मे रखा गया और बारह वर्ष मुकदमा लडने के बाद मै न्यायालय स छूटा। चावल न सरकारी था न राशन का । मुझ पर आरोप था कि कानून के अनुसार कोई भी उपभोक्ता अपने घर मे एक सौ किलो से ज्यादा चावल नही रख सकता था। इसी एक्ट के नाम पर कसाई जैसे कानून बनाकर नागरिको को जबह करने मे इन नेताओ को मजा आता था। पांच बोरा सरसों बिना रजिस्टर मे लिखे रखने के आरोप मे वर्षो मे जेल मे रखने के कई उदाहरण मौजूद है। आज भी छत्तीसगढ का कोई किसान अपने खेत का गन्ना काटकर गुड बना ले तो इतना कठोर दण्ड मिलेगा जैसे कि उसने कही डाका डाल दिया हो। अपने खेत की लकडी बिना अनुमति के काट लेना भी बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी मे शामिल रखा गया है। लकडी जप्त, गाडी जप्त, अपराधी की जमानत नही । सिद्ध है कि लकडी आपके खेत की है , जंगल की नहीं किन्तु बिना सरकारी अनुमति के लकडी काटकर आपने दुनियां के पर्यावरण को खतरे मे डालने जैसा गंभीर अपराध किया है। दूसरी ओर इस कानून बनाने वालों ने अपने लिये करोडो अरबों के चौडे चौडे दरवाजे खोल रखे थे। ये कानून बनाने वाले ही जब कानून के जाल मे फंस रहे है तो इन्हे नैतिकता की दहाई देनी पड रही है। बकरे की गदन पर छुरी चलाने और उसी छुरी से कसाई की उगंली कटने के बीच का अंतर इन नेताओ को महसूस होना शुरू हुआ है।

चाहे राहुल, सोनियां, गडकरी, वाड्रा, खुर्शीद आदि दांव पेच करके कानून की नजर मे ससम्मान मुक्त हो जावे किन्तु समाज की नजर मे वे उसी तरह अपराधी है जिस तरह मेरे जैसा चावल सरसो लकडी गन्ना के मामले मे कानूनी अपराध करने के बाद भी समाज की नजर मे निर्दोष ओर सम्मानित है। इन सामाजिक अपराधियो की छटपटाहट हमारे दिलो को शकून देती है। हमे तो खुशी होगी जब हमारे लिये मकडी का कानूनी जाल बुनने वाला स्वयं उस जाल मे फसेगा। और तब हम इन नताओ को कहेंगे कि भले ही देर है किन्तु अंधेर नहीं।

इस सप्ताह एक नया घोटाला प्रकाश मे आया कि अकेले महाराष्ट्र प्रदेश मे ही कुपोषित बच्चो के भोजन मे दस अरब का भ्रष्टाचार हुआ। देश के अन्य अनेक प्रदेशो मे भी कमोबेस बच्चो के भोजन मे घोटाला हुआ है। किन्तु अभी उनकी रिर्पोट सार्वजनिक नही हुइ है । एक प्रदेश का

घोटाला अरबों का और वह भी कुपोषित बच्चो के भोजन मे और वह भी सरकारी अनुदान का । किस प्रकार बडे बडे कारपोरेट घरानों की महिलाओ ने अपने परिवार मे ही महिला स्व सहायक समूह बनाकर ठगा वह असमान्य घटना ही मानी जायगी। मुझे मालूम है कि कुपोषित बच्चो या महिलाओं ने भी कभी ऐसी सहायता की मांग नही की। कारपोरेट घराने मीडिया कर्मियों को पैसा देकर कुपोषण जैसी समस्या को बढा चढाकर वीभत्स स्वरूप मे स्थापित करते है। इन मीडिया कर्मियों और पेशेवर एन जी ओ वालो की मांग पर झूठ मूठ पसीजकर राजनेता कुपोषण दूर करने को प्राथमिकताओं मे शामिल करते है। न्यायालय ऐसे कार्यो का भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिये कुछ नये स्व सहायता समूह बनवाने का नाटक करता है। और बस शुरू हो जाता है कुपोषण के नाम पर लूट का खेल जिसमे नेता अफसर न्यायाधीश मीडिया तथा एन जी ओ का अपना अपना भाग शामिल हो जाता है। इन तथा कथित आंसू बहाने वालों ने आज तक कभी यह क्यो नही पूछा कि कुपोषण के लिये अरबों खरबो का खर्च होने वाला बजट कहां से आता है? क्या यह बजट ही कुपोषण का कारण नहीं है? गांव मे दिनभर बीडी पत्ता तोडने वाले श्रमिक से आधा बीडी पत्ता टैक्स रूप मे वसूलना कुपोषण का कारण नही है? गांव मे पैदा आवला गोंद आदि से टैक्स चूसकर कुपोषण दूर करने का नाटक क्या इन सबका षडयंत्र नही है? क्यो नही न्यायालय यह प्रश्न करता है कि कुपोषण दूर करने के लिये एकत्रित धन मे से कितना पैसा गरीब ग्रामीण श्रमजीवो छोटे किसान से टैक्स के रूप मे आता है? मीडिया ' या विद्वान लेखक यह प्रश्न क्यो नही उठाते ? स्वाभाविक है कि इस तरह गरीब ग्रामीण श्रमजीवी छोटे किसान से धन लेकर उसे कुपोषण दूर करने के नाटक के पीछे इन सबका स्वार्थ छिपा है। अब धीरे धीरे ये भेद खुलने शुरू हुए है। आगे आगे देखिये होता है क्या?

इस सप्ताह ही एक नई घटना के अन्तर्गत गडकरी जी ने स्वामी विवेकानंद और दाउद इब्राहिम की तुलना करते हुए कह दिया कि दाउद और विवेकानंद लगभग समान बुद्धिवाले थे किन्तु जहां स्वामी जी ने अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके दुनियां मे एक सम्मानजनक महापुरूष का स्थान पाया वहीं दाउद ने अपनी बुद्धि का दुरूपयोग करके एक बदनाम शांहशाह का स्थान पाया। यह आपके स्वयं के उपर निर्भर है कि आप अपनी बौद्धिक क्षमता का कहां और कैसे उपयोग करते है। यह टिप्पणी सामने आते ही एक राजनैतिक तूफान खडा हो गया। विपक्ष ने तो इस टिप्पणी को विवेकानंद का अपमान बताया ही किन्तु नरेन्द्र मोदी समर्थक भाजपाई गुट भी चोरी छिपे टिप्पणी के खिलाफ हवा देने मे सक्रिय हो गया। ऐसा लगा जैसे कि बस तत्काल ही गडकरी जी की कुर्सी जाने वाली हैं । एक दिन मे ही चारो ओर से गडकरी के खिलाफ छीटाकशी शुरू हो गई । गडकरी जी के खिलाफ सप्रणाम भ्रष्टाचार या आर्थिक अनियमितता के आरोपो की गति इस विवेकानंद के खिलाफ आधारहीन टिप्पणी के समक्ष बहुत कम थी। मैने तिल का ताड बनते तो कई बार देखा है किन्तु बिना तिल का ताड बनने की यह घटना भी प्रत्यक्ष दिख गई।

मै तो नही समझ पाया कि गडकरी जी के इस कथन मे विवेकानंद के अपमान का भाव कहां छिपा है? क्या राम और रावण की तुलना नहीं होती? यदि कोई कह दे कि रावण राम से भी ज्यादा प्रकाण्ड विद्वान था तो इसमे राम का अपमान कहां हुआ? राम की विद्वता ने कभी राम को महापुरूष नही बनाया। राम को महापुरूष बनाया, राम द्वारा अपनी विद्वता के मानवहित मे उपयोग के द्वारा । इस संबंध मे गडकरी जी ने स्वामी जी और दाउद की समानता नही दिखाई । बल्कि इस संबंध मे तो उन्होने दानो के बीच आकाश पाताल का अंतर किया है। मुख्य प्रश्न यह है कि गडकरी जी की इस वैचारिक टिप्पणी को ऐसा भावनात्मक तूफान का स्वरूप कैसे मिला। वास्तव मे हमे इसके पीछे संघ की पृष्ठभुमि पर विचार करना होगा। संघ ने अपने सम्पूर्ण कार्य काल मे ऐसी ही भावनात्मक हवा का उपयोग करने का काम किया। संघ ने स्वतंत्रता के बाद लगातार यह प्रयत्न किया कि भाजपा का कोइ भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्र हैसियत का निर्माण न कर सके। संघ ने हमेशा प्रयत्न किया कि भाजपा का हर चोटी का नेता संघ का मुखापेक्षी ही हो। संघ ने अटल विहारी वाजपेई को लगातार कमजोर करने की मुहिम चलाई और अडवाणी को आगे किया। यदि संघ ने अटल जी के खिलाफ वातावरण न बनाया होता तो सन दो हजार चार मे अटल सरकार जाती ही नहीं । उसी संघ ने अडवाणी के जिन्ना संबंधी बयान को इतना भावनात्मक मुद्दा बना दिया जैसे कि एकाएक कोइ बडा भारी भेद खुल गया हो। आडवाणी को पटकनी देकर गडकरो के कंधे पर हाथ रखा गया किन्तु नरेन्द्र मोदी ने संघ के समानान्तर एक स्वतंत्र योग्यता स्थापित कर ली जो संघ के हर दांव पेच को बखूबी जानता मानता है। संघ गडकरी और मोदी के बीच असमंजस मे था कि गडकरी के भ्रष्टाचार ने संघ को परेशान कर दिया। संघ ने गडकरो से दूरी बनाई किन्तु मोदी ने विवेकानंद दाउद प्रकरण को जिस तरह उठाया वह तरीका न संघ को पसंद आया न किसी और को। यह प्रकरण उठाना सर्वथा गलत था। किसी वैचारिक टिप्पणी को तोड मरोड कर भावनात्मक उबाल पैदा करना संघ की फितरत तो रही है किन्तु उचित मार्ग नहीं । जब मादी जी ने वही वार किया तो मजबूर होकर संघ पूरी ताकत से गडकरी के पक्ष मे खडा हुआ। सच्चाइ यह है कि गडकरी को भ्रष्टाचार मामले मे गुरू मूर्ति जी के माध्यम से क्लीन चिट देकर संघ ने भाजपा का आपसी टकराव टाल दिया है किन्तु संघ की इमानदार छवि पूरी तरह तार तार हो गई है। भविष्य मे संघ अपनी इमानदारी का चाबुक इन भ्रष्ट नेताओ के खिलाफ उपयोग नही कर सकेगा। दूसरी ओर संघ को गडकरी की एक टिप्पणी पर पैदा भावनात्मक उबाल के द्वारा यह भी सोचना होगा कि जिस भावनात्मक उबाल के सहारे वह दूसरो के खिलाफ तूफान खडा करता है उसका दूसरे भी दुरूपयोग कर सकते है।

मुझे याद है कि कुछ वर्ष पूर्व मैने पंडित नेहरू और गोडसे की तुलना करते समय एक वैचारिक टिप्पणी की थी। वह टिप्पणी ज्ञान त्तव अंक 145 सोलह से इक्तीस दिसम्बर दो हजार सात मे छपी जो इस प्रकार है।

(यह यथार्थ है कि गोडसे ने गांधी की हत्या की। जिस साम्प्रदायिक विचारधारा ने गोडसे को प्रेरित किया, गोडसे उस विचारधारा का शिकार हुआ। गोडसे के मन में निस्वार्थ देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। गोडसे की भावना पर कभी कोई उंगली नही उठाई जा सकती। गांधी हत्या के बाद जिस राजनैतिक विचारधारा ने भारत की राजनैतिक व्यवस्था अपने हाथ में की उन सबकी अपेक्षा गोडसे के मन में देशभक्ति की भावना अधिक थी और राजनैतिक स्वार्थ की शून्य। किन्तु राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत नवयुवक''गोडसे'' ने जो किया उस कृत्य से देश की हत्या हो गयी। उसका यह कार्य भले ही देशभक्ति की नीयत से किया गया किन्तु देश और समाज को अपूर्णनीय क्षति तो पहुंचा गया। पिता की नाक पर बैठी मक्खी को तलवार से उड़ाने की मूर्खता करके पिता की हत्या करने वाले मूर्ख या नासमक्ष को और क्या कहा जाए। गोडसे ने बहुत नुकसान किया। गांधी हत्या होते ही स्वार्थी राजनेताओं की बाधा दूर होगी। ये राजनैतिक बिरादरी के लोग गांधी जी को कभी पसंद नहीं करते थे। किन्तु इनको मजबूरी थी। गोडसे की मूर्खता ने इनकी बाधा दूर कर दी। इन सबने गांधी जी के ग्राम स्वराज्य की परिभाषा बदल दी। इन सबने सत्ता को अपने स्वयं के लिए तथा अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए रिजर्व करने का खेल शुरू किया। आज तक भारत उस खेल से मुक्त नहीं हो सका। इन नेताओं को भारत की सामाजिक राजनैतिक व्यवस्था में अपने स्वार्थ पूर्ति का अवसर दिया गोडसे की एक भूल ने। यदि गोडसे और बाद के राजनेताओं के कार्यों की समीक्षा करें तो हम पायेंगे कि बाद के लोगों ने भी जो किया वह गोडसे के कार्य से कम गांधी विरोधी नहीं है भले ही भिन्न प्रकृति का है। किसी मूर्ख की मूर्खता का लाभ चालाक लोग उठा लें तो समीक्षक को समीक्षा करने मे जो कठिनाई होती है वही कठिनाई मेरे समक्ष भी है। गांधी जी के बाद राजनीति से ग्राम स्वराज्य लोक स्वराज्य के प्रयोग को निकाल बाहर कर दिया गया। नासमझ गांधीवादियों को समाज निर्माण के काम में भेज दिया गया। भारत को गाांधी हत्या के कारण जो क्षति उठानी पड़ी वह अब भी यथावत जारी है। अब भी गांधी विचारों को दूर करके राजनैतिक स्वार्थ की

विरासत समाज व्यवस्था पर मजबूत पकड बनाए हुए हैं। यदि आज गोडसे जीवित होता तो अपने किये के पश्चाताप से पागल हो जाता। गोडसे ने जो तर्क गांधी हत्या के पक्ष में उस समय दिये आज उनके बिल्कुल विपरीत तर्क देता क्योंकि गोडसे से भूल हुई जो उसे समझ में अवश्य ही आती। मैं महसूस करता हूं कि यदि गोडसे के समान निस्वार्थ युवक साम्प्रदायिक दिशा में न जाकर गांधी के सम्पर्क में आया होता तो इस देश की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता। फिर देश गांधी हत्या के कलंक से बच जाता। फिर देश की राजनीति पर सत्तालोलुप नेताओं का कब्जा नहीं होता। फिर गांधीवादी ग्राम स्वराज्य, लोकस्वराज्य की दिशा से भ्रमित नहीं होते। और भी बहुत कुछ संभव था जो नहीं हो सका। अब भी समय है कि हम नई पीढ़ी क देशभक्तों को गुमराह होने से बचा लें अन्यथा फिर से ये देशभक्त गुमराह होकर कोई भूल कर बैठे तो फांसी उस भूल के दुष्परिणामों से बचाने का समाधान न आज तक हुई है न होगी।)

मेरी इस वैचारिक टिप्पणी पर बवाल हुआ। कांग्रेस के लोगो ने इस टिप्पणी को नेहरू जी के विरूद्ध माना तो कुछ ने गांधी जी का अपमान । मेरे एक निकट के साथी तो इतने नाराज हुए कि उन्होने मेरा साथ ही छोड दिया किन्तु मैने टिप्पणी वापस नही ली क्योकि मै उस समय भी सही था और आज भी। फिर मुझे कोई गडकरी जी के सामान अध्यक्ष पद की मजबूरी भी नही थी जो मुझे बिना गल्ती के क्षमा मांगने को विवश करती। गडकरी जी ने क्षमा मांगकर बवाल ठंडा कर दिया तो संघ ने बवाल के बहाने गडकरी जी के भ्रष्टाचार के दाग को धो पोछकर साफ करने का अवसर निकाल लिया। मेरे विचार मे ये सब उचित मार्ग नहीं । संघ को चाहिये था कि वह गडकरी जी की वैचारिक टिप्पणी पर उनका बचाव करता और उनके भ्रष्टाचार से स्वयं को किनारे कर लेता। किन्तु किया उसके उल्टा।

अब भी समय है कि संघ भाजपा से स्वयं को मुक्त कर ले । यदि पूरी तरह मुक्त न भी हो तो उसे आशिंक स्वतंत्रता दे अन्यथा भाजपा कभी बालिग नही हो पायेगी और न संघ को लाभ हो पायगा न भाजपा को ।

खबरे इस सप्ताह की 8/11 से 14/11/2012

इस सप्ताह के प्रारंभ मे ही अरविन्द केजरीवाल की टीम ने ब्लैक मनी पर बडा आक्रमण करते हुए स्पष्ट किया कि भारत सरकार को हजारो नामो मे से सात सौ नामो की अधिकृत सूची प्राप्त हो चुको है जिन्होने अपना काला धन विदेशी बैकों मे छुपा रखा है। इस रहस्योदघाटन मे बताये गये कुछ नाम कोई चौकाने वाले नहीं थे। चौकाने वाली बात यह थी कि भारत मे ही कार्य कर रहा एक बैंक इस लेन देन मे माध्यम बना हुआ था। उस बैक के कर्मचारी ही भारतियो के काले धन का लेन देन करते थे जो हवाला के द्वारा विदेशो मे आता जाता रहता था । सबसे ज्यादा चौकाने वाली बात यह थी कि भारत सरकार को उक्त बैक के अवैध कारोबार की अधिकृत जानकारी थी किन्तु सरकार ने कोई ठोस कदम नही उठाया । उससे भी बडी बात यह थी कि सरकार ने सात सौ लोगो मे से छोटे छोटे सौ लोगो पर कार्यवाही की और शेष छ सा पर न कोई कार्यवाही हुई न नाम उजागर किये।

स्पष्ट है कि इन छ सौ नामो मे से कोई ऐसा नाम अवश्य है जो इस सरकार की प्राणवायु के समान ह। सुब्रमन्यम स्वामी ने कई बार ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा किया किन्तु सुबमन्यम स्वामी के कथन मे विश्वसनीयता का अभाव हाने से उनका कथन आगे नही बढ पाया । टीम अरविन्द ने विश्वसनीयता की प्रामाणिकता प्राप्त कर ली है। यही कारण है कि इनकी हर प्रेस कान्फ्रेन्स की श्रोता घन्टो प्रतीक्षा करते पाये जाते हैं। कुछ माह पूर्व तो ऐसे किसी शक्तिशाली परिवार की कल्पना सिर्फ बडे औधोगिक घटानो तक ही जाकर सिमट जाती थी। किन्तु राबर्ट वाड्रा प्रकरण अथवा नेशनल हेरल्ड प्रकरण ने शक की सुई राजनैतिक घरानो की ओर घुमा दी है। लोग बेफोस प्रकारण मे को भूलते जा रहे थे किन्तु इस नये खुलासे ने यह संदेह पैदा कर दिया है कि यह सरकार मरते दम तक उस व्यक्ति का नाम उजागर नही होने देगी। अब जब अरविन्द जी वगैरह ने सध लगानी शुरू कर दी है तो यह खतरा और भी ज्यादा बढ गया है कि सरकार ऐसे महत्वपूर्ण नाम को और भी ज्यादा सुरक्षित रखे ।

मुझे पूरा विश्वास है कि पानी मे मुंह डुबाकर मछली खाने वालों के गले मे मछली फसेंगी ही। तब सरकार के समक्ष नाम उजागर करना मजबूरी हो जायगी। मुझे तो डर है कि जिस तरह टीम अरविन्द की विश्वसनीयता बढ रही है उसमे यदि किसी दिन इन्होने किसी असत्य का ही नाम प्रसारित कर दिया तो जनता आंख मूंद कर उस नाम पर विश्वास करने को तैयार हो जायगी।

इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण घटना क्रम मे कांग्रेस पार्टी की रैली और सुरज कुंड मंथन बैठक भी शामिल रही। कांग्रेस पार्टी के ये दोनो अप्रत्यशित कदम राजनैतिक घटना क्रम के लिये विशेष महत्वपूर्ण है। देश की अर्थव्यवस्था लगातार बिगडती जा रही है। अर्थव्यवस्था को सुधारने के सारे प्रयत्नोंको विपक्ष तथा कांग्रेस के सहयोगी दलो ने प्री तरह रोक रखा है। कांग्रेस के भीतर भी एक तबका है जो ऐसे प्रयत्नों को अलोकप्रिय मानकर दो हजार चौदह तक उनसे बचने की सलाह दे रहा है। कांग्रेस पार्टी लोकप्रिय या परिणाम दायक की दुविधा मे फंसी रही । परिणाम दायक कदम की ओर बढते ही सरकार गिरने का खतरा सामने खडा है। यदि लोकप्रियता के मार्ग पर चलते रहे तो अर्थव्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में चली जायेगी। कांग्रेस पार्टी को एक लाइन लेना उसकी मजबूरी थी। जब तक सोनिया जी पुत्र मोह में पड़कर मनमोहन सिंह को अलोकप्रिय करने को राह पर चलीं तब तक तो बात अलग थी किन्तु अब सोनिया जी भी मनमोहन सिंह के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हैं। इसलिय आर पार का निर्णय आवश्यक था। एफ डी आई, डीजल मूल्य वृद्धि, रसोई गैस नियंत्रण आदि कुछ अप्रत्याशित कदम जिस तेज गति से उठे उनसे स्पष्ट हुआ कि कांग्रस पार्टी लोकप्रियता के भ्रमजाल से मुक्त होकर परिणाम प्राप्त करने के मार्ग पर तेजी से चल पड़ी है। अब उसके समक्ष संसद का सत्र आ रहा है जिसमें उसके समक्ष मध्यावधि का खतरा है। रामलीला मैदान रैली और सूरजकुन्ड बैठक से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी मध्यवधि का खतरा भी उठाने को तैयार है। यदि साम दाम दण्ड भेद का उपयोग करके किसी तरह सरकार बच जाये तो ठीक अन्यथा यदि गिर भी जाये तो कांग्रेस पार्टी उस सीमा तक भी अपना मन बना चुकी है किन्तु वह लोकप्रियता के चक्कर में बुरे परिणाम भुगतने का खतरा नहीं उठाना चाहती।

वैसे यदि राजनैतिक संभावनाओं का आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे बुरी स्थिति में है। प्रदेश सरकारें अपनो प्रतिष्ठा के बल बूते भाजपा को चाहे जो सीटें दिलवा दें अन्यथा केन्द्रीय नेतृत्व के भरोसे तो एक भी सीट जीतने का वातावरण नहीं दिखता। छः माह पूर्व नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री पद के मजबूत प्रत्याशी दिखते थे किन्तु पिछले दो तीन महिनों के घटना क्रमों ने उन्हे इस दौड़ से बाहर कर दिया है। नीतिश कुमार की संभावनाएँ तो चुनाव के बाद बनने वाली संसद की तस्वीर पर निर्भर करती है। चुनाव पूर्व वे मैदान में हैं ही नहीं। अब तो टकराव सिर्फ मनमोहन सिंह और अरविन्द केजरीवाल के बीच ही दिखता है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अरविन्द और अन्ना की एकजुटता खंडित होने के बाद अब मनमोहन सिंह के समक्ष कोई संकट उत्पन्न नहीं होगा। यदि भाजपा कोई तुरूप का पत्ता चलकर लोकपाल मुद्दे पर सरकारी बिल का विराध करते हुए अन्ना अरविन्द के जन लोकपाल को अपना बिल घोषित कर दें तथा अरविन्द के दल के साथ राजनैतिक समझौता कर ले तो कांग्रेस के समक्ष एक बड़ी चुनौती बन सकती है। वैसे यह बात बिल्कुल भी संभव नहीं दिखती। इसलिये वर्तमान समय में तो मनमोहन सिंह एक पक्षीय रूप से सफल होते दिखते हैं।

वैसे भी नीतियों के मामले में कांग्रेस के समक्ष भाजपा कहीं नहीं दिखती। कांग्रेस पार्टी ने पिछले सात आठ वर्षों में सूचना का अधिकार तथा नरेगा के रूप में दो मूलभूत परिवर्तन समाज को दिये। दोनों के अच्छे परिणाम दिखे। वर्तमान समय में भी कांग्रेस पार्टी आधार परिचय पत्र तथा कैश सब्सीडी नाम से दो मौलिक बदलाव करने जा रही है। आधार योजना पर तो काम शुरू भी है तथा कैश सब्सीडी योजना की भी अन्तिम घोषणा हो चुकी है। मेरे विचार में कैश सब्सीडी एक क्रान्तिकारी योजना सिद्ध होगी। बीस वर्ष से मैं आधार और कैश सब्सीडी की मांग करता रहा ह्। कांग्रेस पार्टी ने भले भी बीस वर्ष लगाये किन्तु कुछ मूलभूत किया। भाजपा ने न कुछ मौलिक सोचा न किया। सिर्फ सरकार का विरोध करना ही इनकी राजनीति है जो कोई उचित नीति नहीं है। भावनाओ का उबाल लम्बे समय तक नही टिक सकता। इसलिये यह स्पष्ट दिख रहा है कि नीतियों के मामले में कांग्रेस और भाजपा के बीच कोई तुलना नहीं है जिसका लाभ कांग्रेस को दिख रहा है।

मुझे तो लगता है कि टीम सोनिया ने सारी राजनैतिक स्थिति का ठीक ठीक आकलन करके यह महसूस कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी की संभावनाएं बहुत उज्वल हैं। यही सोचकर टीम सोनियां ने मनमोहन के स्थान पर राहुल गांधी को आगे कर दिया है। भविष्य क्या होगा यह कहना तो कठिन है किन्तु यह देश के लिये एक चिन्ता की घडी है कि विपक्ष का अभाव है और सत्तारूढ दल एक परिवार का बंधक है। यह तो लोकतंत्र क नाम पर मजाक मात्र है। क्या होगा यह तो पता नही किन्तु टोम अरविन्द के नाम पर टीम राहुल को कडी टक्कर तो दी ही जानी चाहिये। मेरा व्यक्तिगत मत तो यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के विरूद्ध जो भी मजबूत उम्मीदवार हो चाहे वह किसी भी दल का क्यो न हो उसे मजबूत बनाना ही उचित होगा। टीम सोनिया के तिकडम का स्वस्थ मुकाबला आवश्यक है। इस टीम मे दिग्विजय सिंह जयराम रमेश, अजीत जोगी सरीखों को शामिल करके जो प्रयत्न किया गया है यह चुनौती देश को स्वीकार करनी चाहिये।

उत्तरार्ध

व्यवस्था परिवर्तन मंच भारत

छबील सिंह सिसौदिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

शिविर कार्यालय – प्लाईवुड सेन्टर पबला रोड़ रमपुरा पिलखुआ हापुड उ0प्र0

सेवा में,

राष्ट्रपति महोदय

भारत नई दिल्ली

विषयः– लोक तान्त्रिक व्यवस्था के नाम पर चली आ रही अप्रत्यक्ष तानाशाही केन्द्र के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद एवं सुशील कुमार शिंद के वक्तब्यों से सिद्ध हो रहा है कि असामाजिक एवं अव्यावहारिक मंत्रियों के वक्तब्यों से देश को, अराजकता की आग में धकलने की साजिश दिख रही है।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए निवेदन है कि, डॉ0 जाकिर हुसैन ट्रस्ट में कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी का विकलांगों को दिये जाने वाले यत्रों में धन के घपले का उजगार करना एवं सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा की अकूत सम्पत्ति का उजगार अरविन्द केजरीवाल के द्वारा किये जाने पर सलमान खुर्शीद कानून मंत्री ने केजरीवाल को फरूखखाबाद से कैसे लौटने को चेतावनी दे डाली एवं गृहमंत्री सुशील कुमार सिंद ने अरविन्द केजरीवाल को उक्त दोनों घपले व भ्रष्टाचार का उजगार करने पर आत्म निरीक्षण की सलाह दी, तथा साथ ही केजरीवाल के बयान को समाज अनुशासन हीनता की स्थिति मानकर सहन नहीं करने की चेतावनी दे डाली।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता की सरकार मानी गई है। समाज जन प्रतिनिधि का चुनाव करता है। सरकार समाज का अंग है इसलिए समाज सर्वोच्च है।सरकार के बनाये गये ऐसे कानून, जो समाज का शोषण, उत्पीड़न करते हैं, कटुता उत्पन्न करते हैं व भ्रष्टाचार अपराध का बढ़ावा देते हैं क विरोध में व्यक्ति व समाज सेवी संस्थाऐं ऐसे कानूनों का व भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं।राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में लोकस्वराज्य की स्थापना की मांग की जा रही है। अप्रैल 2011 से भ्रष्टाचार के विरोध की डग्गी पूरे देश में बज रही है लेकिन केन्द्र से लेकर राज्य सरकारों पर कोई असर नहीं, रोज नये घोटाले राजनेताओं के उजगार हो रहे हैं। कोई शर्म नहीं।

लग रहा है कि शासन समाज को अभी गुलाम समझने को मानसिक विकृति पाले हैं। जो स्वतंत्र जॉच एजेन्सी की स्थापना करने को तैयार नहीं तथा न्यायालयों में समय पर न्याय मिले पूर्ण न्यायधीशों की नियुक्ति नहीं। इसलिए कि देरी से न्याय होगा तो भ्रष्ट नेता व नौकर का बचाव आसान होगा।

सत्ताधारी एवं राजनेताओं की विकृत मानसिकता को सम्पूर्ण समाज बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार के विरोध पर जनता को निष्पक्ष जॉच का आश्वासन न देकर सरकार व उसके सहयोगी धमकी भरी भाषा एवं धमकिया भरे व्यक्तव्य देते चले आ रहे हैं।

अतः श्री मान जी से अनुरोध है कि आप राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर हैं। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को दिशा निर्देश करें कि विरोध मे समाज जागृत हो गया है। पुलिस व सेना की सुरक्षा के बल पर बड़े–से बड़ा भ्रष्ट नेता या व्यक्ति इस समाज को अधिक समय तक गुमराह नहीं कर सकेगा।

भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जॉच के लिए उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के जजों की बनी समिति से जॉच कराने की व्यवस्था करें। ताकि लोक तान्त्रिक व्यवस्था बलवत बनी रहे। कष्ट के लिए धन्यवाद।

दिनांकः– 27.10.2012

भवदीय

छबील सिंह सिसौदिया

पिछले कुछ महिनां की परिस्थितियों से स्पष्ट है कि वर्तमान भारत में ''लोक'' ''तंत्र'' पर संम्प्रभुता स्थापित करने हेतु कटिबद्व हैं। राजनोति पर समाज के अंकुश की इच्छा अब उत्तरोतर बलवती हो रही है। इस जन–जागरण का श्रेय भारतीय समाज को तो जाता ही है, साथ–साथ समूची राजनैतिक व्यवस्था की बंदरबांट वृत्ति के खुलासों ने भी इस जन–जागरण को पुष्ट ही किया हैं।

अब भारत की जनता ''सत्ता परिर्वतन'' एंव ''व्यवस्था परिर्वतन'' का भेद जानने लगी है तथा व्यवस्था परिर्वतन की दिशा में कार्यरत समूहों को शक्ति प्रदान करने लगी हैं, चाहे वह ''लोक स्वराज्य मंच'' हो, अन्ना हजारे हों, अरविन्द केजरीवाल हों, या अनेकानेक स्थानीय आन्दोलन।

परिवर्तन की चाह तथा कार्यान्वयन में अतर होता है, क्योंकि चाह नीयत–प्रधान होती है एंव कार्यान्वयन नीति–प्रधान। जयप्रकाश आन्दोलन में भी नीयत ठीक रहीं, नीतियाँ गड़बड़ाई। आज 35 साल बाद फिर ऐसा ही सुनहरा मौका भारत के सामने है, बशर्ते उस समय की नीतिगत त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा जाय तो सम्पूर्ण क्रान्ति निश्चित तौर पर संभव है।

''लोक स्वराज्य मंच'' 1999 से ही व्यवस्था परिवर्तन कार्यान्वयन के नीतिगत मसलों में स्पष्ट रहा है। ''भावी भारत का संविधान'' एंव ''लोक संसद'' के विचार इसके प्रमाण हैं। बदलते भारत को इन विचारों से प्रत्यक्ष परिचय करवाने हेतु ''लाक स्वराज्य मंच'' ने व्यापक जन–चेतना यात्रा 22 नवम्बर 2012 से प्रारंभ की है जो विभिन्न चरणों में देश भर के 100 केन्द्रों में 31 मार्च 2012 तक पूर्ण की जाएगी।

इसी यात्रा के अंतगत ''ज्ञान क्रान्ति अभीयान'' विचार मंथन को भी प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। प्री यात्रा का संचालन– राजीव माहेश्वरी फोनः 09179045559, रमेश कुमार चौबे फोनः 08435023029,, मिल कर करेंगे। आप भी ''लोक स्वराज्य मंच'' के माध्यम से बदलते भारत के नवनिर्माण में सहयोगी बनें तथा आपसे निवेदन है कि आप भी इस यात्रा में अपनी क्षमता अनुसार सहयोग करने की कृपा करें।

–बजरंग मुनि– 09617079344